

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी**  
**पीठासीन अधिकारी श्री रवि वर्मा**

अपील संख्या 20/23

तारीख रजम्- 23.11.23

1. मुरारी पुत्र श्री कान्जी जाति ब्राह्मण गिवासी ग्राम मैडी तहसील वजीरपुर जिला गंगापूर सिटी।
2. श्रीमन पुत्र श्री कान्जी जाति ब्राह्मण गिवासी ग्राम मैडी तहसील वजीरपुर जिला गंगापूर सिटी।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार वजीरपुर तहसील वजीरपुर।

-रिपोर्टर

निर्णय

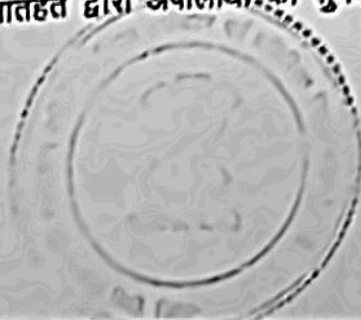
दिनांक- 29/11/2024


अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 120/22 में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मैडी के आराजी खर्च 1310 रुकवा 0.25 हे० कि० म सिद्धायक पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्द्धदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रुयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट की असालतन तामील आज दिनांक दायरी अपील तक नहीं हुई है। फर्जी तामील व फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दिखाकर व अदालत हाजा को गुमराह कर प्रार्थी अपीलान्ट के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही कर उक्त निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है, जो कबिले निरस्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती मानकर सिविल कारावास की सजा देकर कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में भी अपीलान्ट के प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेंसेंकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण



  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं  
गंगापूर सिटी

आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्त द्वारा सिवायकच भूमि पर अतिक्रमण किया गया है यदि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्त की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाये।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सवृत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। जहाँ तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतीचारी होने के प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये अतीचार के संबंध में सुद्वद साक्ष्य या अभिलेख पूर्व में अतिक्रमण संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं निर्णय की प्रति, पूर्व की मौके से बेदखली रिपोर्ट तथा अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किरा खसारे व कितने रकबे पर अतिक्रमण किया हुआ था व पूर्व बेदखली का भी कहीं अंकन नहीं है। मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर सिविल कारावास जैसी कठोर सजा का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सिविल कारावास की सजा के लिए सुद्वद अभिलेख का पत्रावली में अभाव पाया गया है तथा तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक सीडर/2024/19 दिनांक 02.05.2024 के अनुसार उक्त वाद आराजीयात भूमि वर्तमान में खाली है एवं किसी का कब्जा नहीं है। ऐसी अवस्था में सुद्वद अभिलेख के अभाव में पारित किया गया सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से सिविल कारावास की सजा की हद तक स्वीकार की जाती है तथा शेष शरित व बेदखली का आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रवि वर्मा )

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं  
गंगापुर सिटी  
गंगापुर सिटी